

सम्पादकीय

पांच भारत रत्न कुल 53

मोदी ने अब तक पांच लोगों को भारत रत्न से नवाजा है। सभी की जाति प्रदेश और पार्टी अलग अलग है। अब तक भारत रत्न इस पांच सम्हित 53 लोगों को मिल चुका है। एक साथ इन्हें भारत रत्न पहले कभी नहीं दिया गया। लोगों को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। पहली बात यह है कि जिन लोगों को मोदी ने चुना है उनका देश और समाज के लिये बड़ा योगदान है। किसी को नहीं कहा जा सकता कि इस सम्मान लायक नहीं है।

पीछी नरसिंह राव ने अपने वित्तमंत्री मनोहर सिंह के साथ उदारीकरण करके पर्सिट को राज से युक्ती दिलाते हुये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध हटाकर भारत के व्यापार स्थिति को सुधारा और उस समय बिदेसी मुद्रा का भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बढ़ावा देने के लिये इतनी लोगों को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। पहली बात कार्य किसी बदले हो अच्छा ही कहा जायेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मोदी ने चुना है उनका देश और समाज के लिये बड़ा योगदान है। किसी को नहीं कहा जा सकता कि इस सम्मान लायक नहीं है।

पीछी नरसिंह राव ने अपने वित्तमंत्री मनोहर सिंह के साथ उदारीकरण करके पर्सिट को राज से युक्ती दिलाते हुये अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध हटाकर भारत के व्यापार स्थिति को सुधारा और उस समय बिदेसी मुद्रा का भारत में अन्तर्राष्ट्रीय बढ़ावा देने के लिये इतनी लोगों को सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। पहली बात कार्य किसी बदले हो अच्छा ही कहा जायेगा। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को मोदी ने चुना है उनका देश और समाज के लिये बड़ा योगदान है। किसी को नहीं कहा जा सकता कि इस सम्मान लायक नहीं है।

यह जरूर है कि मोदी द्वारा घोषित रत्न का सन्देश बहुत स्पष्ट है। पर पुनर्जागरण को शामल नहीं जाना जायेगा। अच्छे कामों के माध्यम से कोई लोकहित का मिलना पूरा करना निर्णय नहीं हो सकता है। मोदी ने जो पांच भारत रत्न अपील दिये हैं उनका विश्लेषण करें तो कोई अनुचित सम्मान ही बनती है। सभी सुशोधन लोग हैं उनके सम्मान से भारत रत्न का ही सम्मान बढ़ा है।

कपूरी ठाकुर पिछड़ी जाती थी बिहार के मथुरा नेता था उनकी राजनीति सेवा खुलाई नहीं जा सकती। उनके सम्मान से प्रभावित हो निर्तीश ने लालू की पार्टी से किनारा कर मोदी पार्टी का हथ पकड़ लिया। अडवानी जिहाने राम रथ निकालकर राम से इतना भावनात्मक लगाव पैदा कर दिया कि उनके पर्सिट पर अंग्रेजी राम मान्दर का साकार हो गया। अडवानी जिहाने राम से पूरोधा जो संघर्ष वालों को स्पष्ट देने के पक्ष में गया है।

नरसिंह राव जिन्हे उदारीकरण से भारत का नवका बदला उस समय की कागिस ने उन्हें कभी मनसे नहीं अपनाया। न तो उनका सम्मान दिया। यहाँ तक की मरने के बाद उनके दिल्ली में अनिमन क्रिया के लिये अनुमति नहीं दी। द्व्यवहीनता की हड्डी है। नेहरू, इन्द्रा, राजीव को कागिस ने भारत रत्न दिया, नरसिंह राव को इससे मरहम रखवा। चौधरी चरण सिंह को मिला सम्मान किसानों का सम्मान है। अल्पकालिक प्रधानमंत्री अग्र बुझ अवधि तक बन रहे तो किसानों की हालत कापी सुधार दिये होते। चरण सिंह के पोते इन्हे प्रभावित हुए कि सपा का साथ छाड़ भजपा का जान थाम लिया। प्रतिनिधि दोस्रे बन जाये इससे अच्छे कार्य की कसीटी बना हो सकती है। स्वप्नीनाथन हरित क्रान्ति के जन्मदाता जिहाने भारत के कृषि की दशा को सुधारते हुए किसानों में भी हरित क्रान्ति लाली दी उठें तो बहुत पहले यह सम्मान मिल जान चाहिये था। सम्मान के लिये चुने व्यक्तियों के सन्दर्भ में उत्तर दिविखन, पूरब, पश्चिम का लोग ऊर्जेख कर रहे हैं पर यह सम्मान प्रान्तवाद से ऊपर उत्तर एक देश का सन्देश देता है।

कुछ लोग कह रहे हैं इन्हें लोगों के एक साथ सम्मान देकर सर्वोच्च सम्मान की कीमत का जी जारी है। वह उत्तर लगते होने नहीं उत्तरी। आग जाया लोग पर्स्ट डिविजन पायेंगे तो क्या इसलिये खुले लोगों की निकारा जायेगा कि ज्ञाना लोगों को पर्स्ट डिविजन देने से डिविजन की बीमत कम हो जाएगी। उन्हें सोचना चाहिये सम्मान लोगों के लिये होते ही लोग सम्मान के लिये नहीं होते हैं। यह सत्य है कि मोदी का स्वयंभू मास्टर स्ट्रेक्च बन गया है। पर यह तो काम करने की अच्छी है बुरी नहीं। सभी सम्मानियों को बढ़ाइ।

कितनी व्यावहारिक है एमएसपी कानून की मांग?

आशीष बशिष्ठ

दो साल बात किसान फिर से सड़कों पर है। किसानों की मुख्य मांग सभी फसलों पर न्यूट्रिम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गरिटी वाला कानून। किसान सरकार से एमएसपी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

अभी एमएसपी को कानूनी दर्जा हासिल नहीं है। इसका भला लगता है कि वह सरकार पर निर्भर करता है कि वह किसानों को एमएसपी का खाता देगी या नहीं। तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बातों में विजित कानून, 2020 को रह करने, लखनऊ पर्सिट कानून, 2020 को रह करने, एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। एक दोस्रे लोगों को खाता देगी या नहीं। तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बातों में विजित कानून, 2020 को रह करने, एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश से साल 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सोएसीपी का गवर्नर बनाया दिया था। यह साल रबी और खरीद करनी पड़ती है। सरकार जिन 81 कोड लोगों को सफलता के लिए एमएसपी का लागू करने की गई है। केंद्र सरकार फसलों पर एमएसपी का लागू करने की अधिकारी खरीद के लिए एमएसपी का लागू की गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को उचित समेत दिए जाने के उद्देश

